

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष : एम०के०सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक 05-तीन/1989 - विरुद्ध आदेश दिनांक
19-12-1988 - पारित द्वारा - कलेक्टर जिला विदिशा -
प्रकरण क्रमांक 21/1987-88 निगरानी

नारायण सिंह पुत्र झुन्नीलाल दांगी
निवासी ग्राम पीपरहूटा तहसील
व जिला विदिशा, मध्य प्रदेश

-- आवेदक

विरुद्ध

मध्य प्रदेश शासन

---अनावेदक

(आवेदक के अभिभाषक श्री एस०के०अवस्थी)
(अनावेदक के अभिभाषक श्री डी०के०शुक्ला)

आ दे श

(आज दिनांक २ मार्च, 2016 को पारित)

यह निगरानी कलेक्टर जिला विदिशा द्वारा प्रकरण क्रमांक
21/1987-88 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 19-12-1988
के विरुद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के
अंतर्गत प्रस्तुत हुई है।

2/ प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि राजस्व निरीक्षक
वृत्त विदिशा ने अनुविभागीय अधिकारी विदिशा को प्रतिवेदन दिनांक
19-9-85 प्रस्तुत कर बताया कि आवेदक के परिवार में 67.651
हैक्टर (167.04 एकड़) भूमि है जबकि उसे 54 एकड़ भूमि रखने
की पात्रता है। इस पर से अनुविभागीय अधिकारी विदिशा ने कृषि
जोत उच्चतम सीमा अधिनियम के अंतर्गत दिनांक 20-9-85 को
प्रकरण क्रमांक 6 अ-90 (बी-3)/1985-86 पंजीबद्ध किया एवं

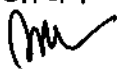




अधिनियम की धारा 10 अनुसार निर्धारित प्रपत्र पर नोटिस जारी करने के आदेश दिये। आवेदक द्वारा दिनांक 30-4-86 को नोटिस का उत्तर प्रस्तुत किया तथा आपत्ति प्रस्तुत की कि पूर्व में उसके विरुद्ध प्र0क0 2003 : 1974-75 अ 90 (बी-3) चला था जिसमें तत्समय पदस्थ सक्षम अधिकारी ने आदेश दिनांक 2-9-76 से आवेदक पर कृषि सीलिंग से अधिक भूमि न होना पाकर प्रकरण समाप्त कर दिया है जिसके कारण इस प्रकरण को भी खारिज किया जाय। अनुविभागीय अधिकारी विदिशा (सक्षम अधिकारी) ने आवेदक को सुनकर अंतरिम आदेश दिनांक 31-5-86 पारित किया एवं आवेदक पर ड्राफ्ट स्टेटमेंट जारी करने का निर्णय लिया। इस आदेश के विरुद्ध कलेक्टर विदिशा के समक्ष निगरानी क्रमांक 21/1987-88 प्रस्तुत हुई, जिसमें पारित आदेश दिनांक 19-12-1988 से निगरानी निरस्त हुई। इसी आदेश के विरुद्ध यह निगरानी है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित तथ्यों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ आवेदक के अभिभाषक का तर्क यह है कि जब आवेदक के विरुद्ध एक बार प्र0क0 2003 : 1974-75 अ 90 (बी-3) में तत्समय पदस्थ सक्षम अधिकारी ने आदेश दिनांक 2-9-76 से कृषि सीलिंग से अधिक भूमि न पाकर प्रकरण निरस्त कर दिया है तब उसी अधिकारी द्वारा उन्हीं आधारों पर पुनः सुनवाई नहीं की जा सकती। अनावेदक के अभिभाषक ने बताया कि जब आवेदक पर प्र0क0 2003 : 1974-75 अ 90 (बी-3) चला था उस समय कृषि सीलिंग से अधिक भूमि नहीं रही होगी, किन्तु जब आवेदक के परिवार में कृषि लिमिट से अधिक भूमि अन्य साधनों से हो गई, तब नवीन प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही प्रारंभ की गई है। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि आवेदक ने वर्ष 1985 से निगरानी करके प्रकरण को 30 वर्ष से अधिक समय गुजार दिये हैं इसलिये प्रकरण का निराकरण शीघ्र किया जाय।

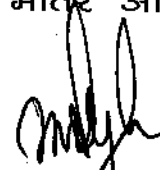




5/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्कों पर विचार करने एवं अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि भले ही आवेदक के विरुद्ध पूर्व में कृषि जोत उच्चतम सीमा अधिनियम के अंतर्गत प्रकरण क्रमांक 2003 : 1974-75 अ 90 (बी-3) चलकर पात्रता से अधिक भूमि न पाकर प्रकरण निरस्त हुआ हो, परन्तु राजस्व निरीक्षक के प्रतिवेदन क्रमांक क्यू/रा0नि0/3/वि/94 दिनांक 19-9-85 अनुसार जांच दिनांक को आवेदक के परिवार में 67.651 हैक्टर अर्थात् 167.04 एकड़ भूमि होना पाई गई है जबकि कृषि जोत उच्चतम सीमा अधिनियम के अंतर्गत धारक केवल 54 एकड़ भूमि रखने की पात्रता रखता है। इन्हीं कारणों से अनुविभागीय अधिकारी (सक्षम अधिकारी) ने आवेदक के विरुद्ध नया प्रकरण दर्ज करके जांच कार्यवाही जारी रखी है। यदि 67.651 हैक्टर अर्थात् 167.04 एकड़ भूमि आवेदक के परिवार को धारण करने की पात्रता है, आवेदक तदनुसार बचाव प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र है जिसके कारण विचाराधीन निगरानी व्यर्थ होना पाई गई है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन पाये जाने से निरस्त की जाती है एवं कलेक्टर जिला विदिशा द्वारा प्रकरण क्रमांक 21/1987-88 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 19-12-1988 विधिवत् होने से स्थिर रखा जाता है। यह प्रकरण वर्ष 1985 से लम्बित बना हुआ है अतः अनुविभागीय अधिकारी विदिशा को निर्देश दिये जाते हैं कि उनके न्यायालय का प्रकरण वापिस प्राप्त होने के दिनांक से तीन माह के भीतर अनिवार्य-रूप से निराकरण करें।





(एम0के0सिंह)

सदस्य

राजस्व मण्डल

मध्य प्रदेश ग्वालियर